



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (II)
PART II—Section 3—Sub-section (II)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 498]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 14, 1985/आश्विन 22, 1907

No. 498]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 14, 1985/ASVINA 22, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर, 1985

गधिसूचना

का. धा. 754 (अ).—पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 73 की उपधारा (1) के अधीन, उक्त उपधारा के खण्ड (i) से (vii) में निर्दिष्ट कम्पनियां, 1 नवम्बर, 1966 को और से, ऐसे क्षेत्रों में, जिनमें उक्त कम्पनियां उस दिन से ठीक पूर्व कार्य कर रही थी, ऐसे निदेशों के अधीन रहते हुए, जो केन्द्रीय सरकार ऐसे कार्य करने के संबंध में समय-समय पर जारी करे, तब तक कार्य करती रहेगी जब तक किसी विधि में या पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश राज्यों तथा चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में संघ (जिन्हें हमें इसके पश्चात् "उत्तरवर्ती राज्य" कहा गया है) के बीच किसी करार में अन्यथा उपबंधित न किया जाए,

और उत्तरवर्ती राज्यों ने परस्पर यह करार कर लिया है कि:

- पंजाब राज्य द्वारा, जैसा कि वह 1 नवम्बर, 1966 के ठीक पूर्व विद्यमान था, ऊपर निर्दिष्ट कम्पनियों में धारित शेयर, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश राज्यों तथा चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में संघ को क्रमशः 54.84: 37.38: 7.19: 0.59 के अनुपात में आवंटित किए जाएंगे।
- हरियाणा और हिमाचल प्रदेश राज्य तथा संघ क्रमशः उन्हें आवंटित शेयर पंजाब राज्य को अन्तरित करेंगे;

(iii) पूर्वोक्त प्रत्येक कम्पनी के शेयरों का मूल्य उन कम्पनियों के लेखापरीक्षित तुलन पत्रों के आधार पर, जैसे कि वे किसी ऐसी तारीख को थे जिस पर सहमति हुई थी, अवधारित किया जाएगा; और

(iv) पंजाब राज्य सरकार उस राज्य को अन्तरित शेयरों के बदले इस प्रकार अवधारित मूल्य के अनुसार अन्य उत्तरवर्ती राज्यों को नकद मंदाय करेगी;

और इस कम्पनी के सामने लिखित रकम पर, कम्पनी के प्रत्येक शेयर के मूल्य के संबंध में, जो नीचे निर्दिष्ट है, भारत सरकार का अनुमोदन प्रत्येक उत्तरवर्ती राज्य को संसूचित कर दिया गया है -

कम्पनी का नाम	निम्नलिखित प्रत्येक तारीख को शेयर समाप्त होने का वाली अवधि मूल्य के लिए तुलन पत्र	मूल्यांकन का अनुमोदन करने वाले भारत सरकार के पत्र की विशिष्टियां
---------------	---	--

दि पंजाब डेरी डेवलपमेंट कार- पोरेशन लिमिटेड	31-3-1967 रु. 4.45	गु. सं. का पत्र सं. 17/ 42/67-एस&आर तारीख 27 अगस्त, 1971
--	-----------------------	--

और पंजाब सरकार ने का नियोजन को दे कि अब पंजाब राज्य को संघाय कर दिया गया है और यह संघायन के प्रयोजन एवं केंद्र सरकार वित्तीय समायोजन पूरा कर दिया गया है।

और एक ही प्राप्ति तथा विनीत समायोजन की राज्य द्वारा ही राज्यों द्वारा पुष्टि हो गई है ;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, हिमाचल प्रदेश अधिनियम, 1970 (1970 का 53) की धारा 38 की उपधारा (2) के साथ पठित पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए—

(क) उत्तरवर्ती राज्यों के बीच उपर निर्दिष्ट करार और दिनांक समायोजनों की पुष्टि करती है ;

(ख) निर्देश देती है कि—

(i) पंजाब सरकार इस अधिनियम के तारीख के पश्चात् असाधारण शीघ्र, पूर्वोक्त कम्पनी के समस्त जापनों और समस्त अनुसूचियों में, जहाँ आवश्यक हो, संशोधन करवावेगी ताकि उनमें कार्य पंजाब राज्य से सीमित रहे ;

(ii) पूर्वोक्त कम्पनी के समस्त जापनों और संगम-अनुसूचियों में प्राप्ति संशोधनों के समस्त अनुसूचीय निशान निशान नहीं रहें और उनमें कार्य उस संशोधन में, जिसको ऐसे संशोधन प्रस्तावों द्वारा पंजाब राज्य से सीमित रहे

(iii) उपखण्ड (II) के उपबन्धों के होने हुए भी, जब तक संशोधित संगम-अनुसूचियों के अनुसार तथा निर्देशक बोर्ड गठित नहीं किया जाता, पूर्वोक्त कम्पनी के निर्देशक बोर्ड में हरियाणा सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार और चण्डीगढ़ प्रशासक द्वारा नियुक्त व्यक्ति निर्देशकों के पद धारण करने रहेंगे, और

(iv) कम्पनी के संशोधित संगम-अनुसूचियों के अनुसार निर्देशक बोर्ड के पुनर्गठन की कार्रवाई में भारत सरकार के गृह मन्त्रालय की अधिनियम 17/82-66 एवं और तारीख 15 फरवरी, 1967 (का. अ. 596, तारीख 15 फरवरी, 1967) उस कम्पनी के संशोधन प्रस्तावों तथा राज्यों ।

[सं. 1-013/3/85-पु. अ. 2]

एन. मार. अ. 2, संशुद्ध संविधान

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 14th October, 1985

NOTIFICATION

S.O. 754(E).—Whereas under sub-section (1) of Section 73 of the Punjab Reorganisation Act, 1966 (31 of 1966), the companies referred to in clauses (i) to (vii) of the said sub-section shall, on and from the 1st day of November, 1966 continue to function in the areas in which the said companies were functioning immediately before that day, subject to such directions as the Central Government may from time to time issue in relation to such

functioning, until otherwise provided for in any law or in any agreement among the States of Punjab, Haryana and Himachal Pradesh and the Union in relation to the Union Territory of Chandigarh (hereinafter referred to as "successor States");

And, whereas the successor States have mutually agreed—

(i) that the shares held by the States of Punjab as it existed immediately before the 1st day of November, 1966, in the companies referred to above shall be allocated to the States of Punjab, Haryana and Himachal Pradesh and the Union in relation to the Union Territory of Chandigarh in the ratio of 54.84 : 37.38 : 7.79 : 0.00 respectively;

(ii) that the States of Haryana and Himachal Pradesh and the Union shall transfer to the State of Punjab the shares allocated to them respectively;

(iii) that the value of the shares of each of the companies aforesaid shall be determined on the basis of audited balance sheets of respective companies as on a date mutually agreed upon; and

(iv) that the Government of the State of Punjab shall make cash payment to the other successor States according to the value so determined in lieu of the shares transferred to that State;

And, whereas approval of the Government of India to the value of each share of the company specified hereunder being taken at the amount noted against it has been communicated to each successor State—

Name of the Company	Balance sheet for the period ending	Value of each share	Particulars of the letter from the Government of India approving valuation.
The Punjab Dairy Development Corporation Limited.	31.3.1967	Rs. 4.4	MHA Letter No. 17/42/67-SR dated 27th August, 1971

And, whereas the Government of Punjab has reported that payment to the other successor States has been made and financial adjustments in accordance with the Ministry of Home Affairs letter aforesaid have been completed:

And, whereas the receipt of the amounts and financial adjustments have been confirmed by the other successor States:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 73 of the Punjab Reorganisation Act, 1966 (31 of 1966), read with sub-section (2) of section 38 of the State of Himachal Pradesh Act, 1970 (53 of 1970), the Central Government hereby—

(a) confirms the agreement and the financial adjustments referred to above among the successor States:

(b) directs that —

- (i) the Government of Punjab shall, as soon as may be after the issue of this notification, cause the memoranda and articles of association of the company aforesaid, amended, where necessary, so as to confine its operations to the State of Punjab;
- (ii) with the requisite amendments in the memorandum and articles of association of the company aforesaid, the company shall cease to be an inter-State body corporate and its operations shall, as from the date on which such amendments take effect, be confined to the State of Punjab;
- (iii) notwithstanding the provisions of sub-clause (ii), until a new Board of Direc-

tors is constituted in terms of the amended articles of association, the persons appointed by the Government of Haryana, the Government of Himachal Pradesh and the Administrator of Chandigarh on the Board of Directors of the company aforesaid, shall continue to hold the office of directors, and

- (iv) as from the date of the reconstitution of the Board of Directors in terms of the amended articles of association of a company the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs No 17/82 66 SR, dated the 15th February, 1967 (S.O. 596, dated the 15th February, 1967) shall cease to have effect in relation to that company.

[No. S-12013/3/85 SR]
S. R. ARYA, Jt. Secy.

